

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, 22 जनवरी, 2022

विषय: कोविड-19 के New Variant 'Omicron' के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 919/USDMA/792 (2020), दिनांक 16 जनवरी, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है:-

1. **Night Curfew:** राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
(Curfew अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट संलग्नक-1 के अनुसार प्रदान की जायेगी)।
2. **Market Opening:** समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
3. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
4. राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
5. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

6. विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार, व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. राजनैतिक रैली/धरना प्रदर्शन की दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
8. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
9. होटलों में स्थित **Conference Hall, Spa and Gym** का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
10. उपरोक्त बिन्दु संख्या-3, 5, 6, 8 एवं 9 में दिये गये प्राविधान को छोड़कर, अन्य-मनोरंजन/ शैक्षिक/सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों की दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
11. जो गतिविधियाँ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 300 व्यक्तियों या स्थान/हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों, इनमें से जो भी न्यूनतम हो, उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2022 से दिनांक 12 फरवरी 2022 तक राजनैतिक दलों को खुले स्थानों/मैदानों पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्तों के अन्तर्गत स्थानों/मैदानों की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों, जो भी कम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी (संलग्नक-2)।
12. **School:** राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे, इस दौरान online classes के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।
13. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
14. शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-18/XXXI(15)G/22-04(सा0)/2020 दिनांक 13 जनवरी, 2022 का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक-3)।
15. **COVID Appropriate Behaviour/Sanitization:** देश भर में 'Omicron' के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
16. **IEC Activities:** कोविड-19 के New Variant 'Omicron' से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।

17. **Vaccination:** राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dose को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।

18. General Directives for COVID-19 Management :

राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा।
- ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
- iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

19. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा :

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जाती है :-

- i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
- ii. Persons with co-morbidities.
- iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
- iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

20. दंड के प्रावधान :

- i. COVID-Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,



(डॉ० सुखबीर सिंह सन्धु)

मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,
(शैलेश बगौली)
सचिव

(संलग्नक-1)

1A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24X7) रहेगी जैसे:

- i. चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
- ii. डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।
- iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers)।
- iv. फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID-19 संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।
- v. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।
- vi. COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, सप्लाय चैन फर्म्स आदि शामिल हैं।
- vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ।
- viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा/स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान।

1B. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24X7):

- i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि।
- ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण।
- iii. डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
- iv. राज्य में नगरपालिका/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।
- v. टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन।
- vi. COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर को अपने व्यावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।

1C. निम्नलिखित गतिविधियां दैनिक रूप (24X7) में अनुमत्य है:

- i. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर-राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
- ii. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC, Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी/होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।
- iii. खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।
- iv. प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।
- v. दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
- vi. पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।
- vii. बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।
- viii. कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।
- ix. कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।
- x. ऑटो-मोबाईल मरम्मत की दुकानें।
- xi. क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान।

उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

1D. परिवहन :

- i. सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra-state and Inter-state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अधीन जारी रहेगा।
- ii. विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारु रूप से चलाने की अनुमति है।
- iii. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT) की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

- iv. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/उतारने की (24x7) अनुमति है।
- v. सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से (24x7) अनुमति है।
- vi. अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने संगठनों/संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत (24x7) अनुमति है।
- vii. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों/टैक्सियों/ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज/टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24x7) दी जाएगी।
- viii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs और COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति (24x7) होगी।
- ix. आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार/स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी कर्मिकों एवं वर्णित संगठन के वाहनों को चलने की अनुमति (24x7) होगी।
- x. सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति (24x7) है।
- xi. सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24x7) है।
- xii. निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति (24x7) है।

1E. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी (24x7) :

- i. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य:-बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेशिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग-आदि।
- ii. कृषि/बागवानी/फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे-खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।
- iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन और आपूर्ति शृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री।
- iv. पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियां।

1F. सरकारी और निजी उद्योग/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संचालन (24x7) के संबंध में :

- i. All Industries in both urban and rural areas shall operate with strict adherence to SOPs and Covid-19 safety protocol.
- ii. जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में SOP का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई/कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।

1G. सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति (24x7) होगी :

- i. सभी निर्माण गतिविधियाँ तथा उनमें कार्यरत वाहन/मजदूरों की आवाजाही को स्थानीय पुलिस/प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(शैलेश बगौली)
सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. ECI/PN/10/2022

Dated: January 22, 2022

PRESS NOTE

ECI extends ban on physical rallies and road shows till January 31, 2022

Relaxation for Physical public meetings of Political parties or contesting candidates for Phase 1 allowed from January 28, 2022 and for Phase 2 from February 1, 2022

Limit of 5 persons for door to door campaign enhanced to 10 persons

Video vans for publicity permitted at designated open spaces with COVID restrictions

The Election Commission of India today held a review meeting with the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India through virtual mode. The Commission also held virtual meetings with Chief Secretaries, Chief Electoral Officers and Health Secretaries of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh.

Chief Election Commissioner Shri Sushil Chandra along with Election Commissioners Shri Rajiv Kumar and Shri Anup Chandra Pandey accompanied by Secretary General and concerned Deputy Election Commissioners held a comprehensive review of the present situation with respect to status and projected trends of COVID pandemic in the five poll going states. The Commission also reviewed Vaccination status and action plan for expeditiously completing vaccination for 1st, 2nd and booster dose for eligible persons amongst polling personnel. The Commission deliberated on relaxing restrictions for physical rallies in the wake of prevailing situation.

After taking into consideration inputs and ground reports from these officers, the Commission also deliberated on requirements of the campaign period in phases where candidate list will be finalised on January 27, 2022 for Phase 1 and on January 31, 2022 for Phase 2 .

After considering the present situation, facts and circumstances as also the inputs received in these meetings, Commission has decided as follows:

(1) No road show, Pad-yatra, cycle/bike/vehicle rally and procession shall be allowed till January 31, 2022.

(2) Since contesting candidates for **Phase 1 elections** will be finalised on January 27, 2022, Commission has decided to allow physical meetings of concerned Political parties or contesting candidates in **designated open spaces** with a maximum of 500 persons or 50% of the capacity of the ground or the prescribed limit set by SDMA, whichever number is lesser, **from January 28, 2022 till February 8, 2022 (excluding the silence period).**

(3) Since contesting candidates for **Phase 2 elections** will be finalised on January 31 2022, Commission has decided to allow physical meetings of concerned Political parties or contesting candidates with public in **designated open spaces** with a maximum of 500 persons or 50% of the capacity of the ground or the prescribed limit set by SDMA, whichever number is lesser, **from February 1, 2022 till February 12, 2022 (excluding the silence period).**

(4) The Commission has also enhanced the limit of door to door campaign. Instead of 5 persons, now 10 persons, excluding security personnel, will be allowed for door to door campaigns. Other instructions on door to door campaigns will continue.

5) Commission has already granted relaxation for the political parties to the extent that indoor meetings of a maximum of 300 persons or

50% of the capacity of the hall or the prescribed limit set by SDMA is allowed.

(6) Commission has also allowed video vans for publicity with usual COVID restrictions at designated open spaces with a maximum of 500 viewers or 50 % of the capacity or the limit set by SDMA, whichever number is lesser, in the poll going States subject to public convenience and no hindrance to smooth flow of traffic. (Instructions in this regard are being sent to the CEOs separately).

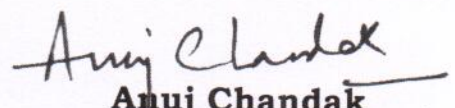
(7) Political parties and contesting candidates shall ensure the compliance of COVID appropriate behaviour & guidelines and Model Code of Conduct at all occasions during the activities connected with elections.

(8) It shall be the responsibility of the DEO concerned to identify and to notify the designated spaces in advance for the aforesaid purposes.

(9) All remaining restrictions as contained in the Revised Broad Guidelines for Conduct of Elections, 2022 issued on January 8, 2022 shall continue to operate.

All concerned State/District authorities shall ensure full compliance of these instructions.

The Commission will review these instructions at a subsequent date.


Anuj Chandak

Joint Director (Media)



**Conduct of General
Elections/Bye-elections
during
COVID
Revised Broad Guidelines
2022**



ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

www.eci.gov.in

**Conduct of General
Elections/Bye-elections during
COVID**

Revised Broad Guidelines

2022

Election Commission of India

Conduct of General Elections/Bye-elections during COVID

Revised Broad Guidelines, 2022

Election Commission of India, on 21st August 2020, had issued "Broad guidelines for conduct of General Elections/Bye-elections during COVID-19". The General Elections to legislative assemblies of Bihar, Tamil Nadu, Kerala, Assam, West Bengal and Puducherry were conducted accordingly. The Commission had also issued further instructions, from time to time, in view of the emerging COVID circumstances and advisories issued by Ministry of Home Affairs and MoHFW.

2. **Article 172(1) of the Constitution of India** states that the term of the legislative assembly shall be five years from the date of its first meeting. The term of state assemblies of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa and Manipur is due to expire starting from 15.3.2022. The relevant provisions of The Representation of Peoples Act, 1950, and The Representation of Peoples Act, 1951 govern the electoral process.
3. **Commission held consultations with all National and State Political parties** in all the poll going states who suggested that elections should be held in time while enforcing the covid appropriate behavior.
4. **Commission also held consultations with Union Home Secretary, Union Health Secretary and Medical experts, Chief Secretaries and Health Secretaries of all poll going states regarding prevailing covid situation and measures being taken/ planned by them.**
5. **The safety of vote and voters**, both are equally and critically important in the democracy. Therefore, it is duty of the Commission to fulfil its constitutional mandate and those of Authorities/ Committee(s) under the Disaster Management Act, 2005 (DM Act) to extend support as per legal and institutional framework to steer elections even during unprecedented pandemic for putting elected government in place within due time.
6. **The Disaster Management Act, 2005 (DM Act)** provides for the effective management of disaster(s) and for matters connected therewith or incidental thereto. A comprehensive institutional regime has been set up under the DM Act with National Disaster Management Authority(**NDMA**) at the Apex level u/s 3(1), National Executive Committee (**NEC**) u/s 8(1), State Disaster Management Authority (SDMA) u/s 14(1), State Executive Committee (**SEC**) headed by the Chief Secretary of the State u/s 20(1) and the District Disaster Management Authority headed by District Magistrate u/s 25(2a). The DM Act mandates and makes such designated Authorities/Committee(s) responsible to prepare plan; prescribe regulatory/ mitigation regime and enforcement thereof; seek community/ inter agency coordination and to monitor implementation of the prescribed directions to contain, mitigate, control damage and providing assistance to the effected persons. The DM Act also empowers the designated authorities/ Committee(s) to take appropriate legal/ punitive action against violators of its directions u/s 51-60 of the Act.
7. Commission, after briefing by the Chairperson of the NEC and the Chairpersons of the SECs of the five poll going states, took note of the action being taken from time to time by such designated authorities / Committee(s) under the legal / institutional mechanism created by the DM Act, 2005. With respect to the

pandemic caused by Covid 19 and subsequent variants of the same, implementation of the Covid appropriate behavior as per the regime prescribed by such designated Authorities / Committee(s) assumes criticality during the electoral process. In view of Variant of Concern (VOC) named as Omicron notified by MoHFW and the prevailing situation, the Commission has examined its existing guidelines and hereby, in supersession of all its earlier guidelines on the subject, further revises/ modifies its broad guidelines comprehensively **to complement and not repeat not to substitute** the mandate/ responsibility of the Authorities/ Committee(s) under the Disaster Management Act, 2005 (DM Act).

8. The Commission directs that during electoral process Chief Secretary at State level and District Magistrate at District level, shall be primarily responsible for monitoring, supervision and strict enforcement of these COVID guidelines and the guidelines issued by NDMA and respective SDMA/DDMA, whichever is more stringent.

Details of the broad guidelines are as follows:

I. Campaign by the political parties/contesting candidates/Others

1. It is expected that all stakeholders namely political parties, candidates, campaigners, voters and authorities engaged in the election process shall always be conscious of their prime duty towards public health / safety and therefore shall abide by these general instructions and other norms of Covid appropriate behavior as mandated by the respective authorities prescribed under the law.
2. **No road show, Pad-yatra, cycle/bike/vehicle rally and procession** shall be allowed till 15 January, 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly.
3. **No physical rally** of Political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15 January, 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly.
4. **However, physical rallies during the campaign period, as and when permitted after the decision of the Commission** shall be conducted subject to adherence to extant COVID-19 guidelines. **The maximum limit of persons allowed for Indoor and outdoor rally/meeting** shall be as per existing direction of respective SDMAs. For these meetings political parties shall distribute masks and sanitizers to persons attending and maintain COVID protocol at entry and exit point.
5. District Election Officer should take following steps for this purpose:
 - I. District Election Officer should, in advance, identify dedicated grounds for public gathering with clearly marked Entry/Exit points.
 - II. In all such identified grounds, the District Election Officer should ensure that markers for social distancing norms are put in place in advance by organisers of the meeting/rally.
 - III. District Election Officer and District Superintendent of Police should ensure that the number of attendees do not exceed the limit prescribed by State Disaster Management Authority for public gatherings. DEO should depute Nodal Health officers to oversee that

COVID-19 instructions/guidelines are followed during these meetings.

- IV. The political parties and candidates concerned shall ensure that all COVID-19 related requirement like face masks, sanitizers, thermal scanning etc. are fulfilled during each of election related activities.
6. Further, rallies and meeting shall be allowed **only in earmarked places** and with prior permissions of district administration.
 7. **Each political party/candidate shall furnish an undertaking** in the application form (under Suvidha) that it shall abide by all the extant instructions/guidelines in this regard.
 8. Allocation of public spaces must be done using Suvidha app in the manner already prescribed by Commission.
 9. **Between 8 pm and 8 am no rallies and public meetings (akin to campaign curfew)** shall be allowed on any campaign day.
 10. **Nukkad Sabhas (meeting) will not be allowed** on public roads, roundabouts or public streets or corners.
 11. Further, Political parties and candidates are advised to conduct their **campaign as much as possible through digital/virtual/ media platforms /mobile based mode** instead of physical mode ensuring strict compliance of Covid safety norms.
 12. **Door to Door Campaign-** A maximum of 5 (five) persons including candidate, excluding security personnel, if any, shall be allowed to do door to door campaigning.
 13. **The convoy of vehicles shall be broken after every 5** (five) vehicles and interval between two sets of convoys of vehicles should be half an hour instead of gap of 100 meters. (In supersession of Para 5.8.1 of Returning Officer's Handbook 2019). During the permitted campaign period, convoy of vehicles will be allowed only for movement of vehicle from one point to another point for campaigning.
 14. **The maximum number of star campaigners** for recognized National/State political parties has been fixed 30 in place of 40, for unrecognized political parties 15 in place of 20. Request for permission for campaign by star campaigners may be given at least 48 hours before the start of campaign to make all necessary safety arrangements.
 15. **No victory procession** after the counting shall be allowed and not more than two persons shall be allowed to accompany the winning candidate or his/her authorized representative to receive the certificate of election from Returning Officer.
 16. **If a candidate or political party violates any of the above guidelines**, no further permission shall be given to the concerned candidate/party for rallies, meetings etc.
 17. The Commission on 29th December, 2021 has directed Secretary, MoHFW to issue direction to treat all eligible govt. officials, deployed/engaged for elections, at par with Front Line Workers (FLWs) in the poll going states and to give them additional precaution dose of COVID-19.

- II. **General Guidelines to be followed during entire election processes for all persons**
18. All person involved with the electoral process shall **wear face mask** during the concerned election related activities.
 19. **Social distancing norms** shall be strictly abided by all persons connected with election related activities as per the extant COVID guidelines of the State Govt. and Ministry of Home Affairs.
 20. All Polling Personnel/Security Personnel/Counting Staff shall be doubly vaccinated before deploying/engaging in election related activities.
 21. No Polling Agent/ Counting Agent etc. allowed to enter Counting hall/polling station without doubly vaccination.
 22. No person shall be allowed to enter Counting hall without double vaccination and if they are not vaccinated/single vaccinated, RT-PCR/RAT from authorized lab will be required within 48 hours from start of polling/counting.
 23. At the **entry of hall/ room/ premises** used for election purposes:
 - **Thermal Scanning** of all persons shall be carried out;
 - **Sanitizer** shall be made available on all entry points.
 24. As far as practicable, large halls should be identified and utilized to ensure social distancing norms.
 25. Adequate number of vehicles shall be mobilized for movement of polling personnel, security personnel to ensure compliance of COVID-19 guidelines.
 26. Create awareness among the public for COVID appropriate behavior including self-monitoring.
 27. **Nodal Health Officer:** Nodal Health Officer shall be designated for the State Level, the District Level and the Assembly Constituency Level to oversee COVID related arrangements and, preventive measures during entire electoral process.
 28. **EVMs/VVPATs**
 - i. First & Second randomization and preparation of EVMs/VVPATs shall be done in large halls.
 - ii. Sanitizers shall be provided in sufficient quantity for use during the process.
 - iii. Gloves shall be made available to each official handling EVM/VVPAT.
 29. **Election Material:** Election Material Kit will be prepared in a spacious and sufficiently large hall following all safety, sanitation and social distancing measures.
 30. **Distribution and Collection of Election Material**
 - i. Large halls/spaces should be identified for distribution/collection of election material.
 - ii. As far as practicable, it should be organized in decentralized manner.
 - iii. Prior time should be allocated to the polling teams for distribution/collection of election material.

31. **Timing of 3rd randomization of Polling Staff:**

Timing for 3rd randomization of polling staff be increased **from 24 hrs to 72 hrs.** in order to avoid large gathering of polling staff at dispatch centres.

(This is in supersession of **ECI No. 464/Inst/2008/EPS dated 19th September, 2008**)

32. **Kit for Polling Officer**

The following items shall be provided to every polling official and security personnel (Other than those where PPEs are needed) in addition to other prescribed items:

- i. Mask
- ii. Sanitizer
- iii. Face-Shield
- iv. Gloves

33. **Training and capacity Building**

- i. As far as practicable, training of election officials will be organized in decentralized manner at large halls.
- ii. Training for election officials may be organized through online mode.
- iii. All PPTs, training materials, relevant documents, topic wise video clips, question papers for self-assessment may be uploaded in app/ portal so that any election official can access it as per requirement.
- iv. Sufficient number of Polling/Counting/Poll related staffs shall also be kept in reserve by DEO/RO, to replace in case any polling personnel displays COVID-19 symptoms.

34. **Nomination Process** Following additional options to facilitate online mode are hereby provided:

- i. Nomination form will also be available online on the website of CEO/DEO. An intending candidate may fill in it online and its print may be taken for submitting before the Returning Officer as specified in Form-1 (Rule-3 of Conduct of Election Rules 1961).
- ii. Affidavit may also be filled in online on the website of CEO/DEO and its print can be taken and after notarization it may be submitted along with the nomination form before the Returning Officer.
- ii. Candidate may deposit security money through **online mode** at the designated platform. However, a candidate will continue to have the option of deposit in cash in the treasury.
- iv. Candidate may have the option to seek his/her elector certification for the purpose of nomination online.
- v. Number of persons to accompany candidate for submission of Nomination is restricted to two (2). (This is in supersession of 5 (five))

as per the existing **Para 5.8.1 of Returning Officer's Handbook 2019**).

- i. Maximum number of vehicles for the purposes of nomination is restricted to two (2) (This is in supersession of the existing **Para 5.8.1 of Returning Officer's Handbook 2019**)
- ii. Returning Officer's chamber should have sufficient space to perform the functions of nomination, scrutiny and symbol allocation following social distancing norms.
- ii. Returning Officer should allot staggered time in advance to prospective candidates.
- x. Large space for waiting for candidate(s) should be arranged.
- x. All steps required to be taken for the submission of nomination form and affidavit shall continue to operate as per the provisions contained in the Representation of the People Act, 1951.

35. **No. of electors in Polling Station**

There shall be maximum 1250 electors instead of 1500 electors in a polling station.

36. **Polling Station Arrangements**

Commission has issued detailed instructions for assured minimum facilities at each polling station. Now, in view of COVID situation, following additional facilities/steps should be taken:

- i. Mandatory sanitization of Polling Station, preferably, a day before the poll.
- ii. Thermal Scanner at the entry point of every polling station location.
- iii. Thermal Checking of voters at entry point of polling station location/Polling station, either by polling staff or Para Medical staff or Asha worker.
- iv. **If temperature is above the set norms of MoH&FW at first reading, then it will be checked twice and if it remains, then the elector shall be provided with token/certificate and will be asked to come for voting at the last hour of poll. At the last hour of poll, such electors shall be facilitated voting, strictly following COVID-19 related preventive measures.**
- v. Help Desk for distribution of token to the voters of first come first basis so that they do not wait in the queue.
- vi. Marker to demonstrate social distancing for queue.
- vii. Earmarking circle for 15-20 persons of 2 yards (6 feet) distance for voters standing in the queue depending on the availability of space. There shall be three queues each, for male, female, and PwD/ Senior citizen voters.
- viii. The services of BLOs, volunteers etc may be engaged to monitor and regulate social distancing norms strictly.
- ix. One shaded waiting areas with chairs, dari etc. will be provided, for male and female separately, within the polling station premises so that voters can participate in voting without safety concerns.

- x. Wherever possible, Booth App shall be used at the polling station.
- xi. **Sanitizer** should be provided at the entry/exit point of every polling station.
- xii. **Face Masks** in reserves for those electors who are not carrying the mask will be kept.
- xiii. Awareness posters on COVID should be displayed at visible locations.
- xiv. Sitting arrangement in polling station for the polling personnel and polling agents shall be made as per the norms of social distancing.
- xv. If polling agent or counting agent is having temperature above the prescribed limit, then their reliever shall be allowed by Presiding Officer, who will keep a record accordingly.
- xvi. During the process of identification of voter, the voters will require to lower the facemask for identification, when required.
- xvii. At any given time, only 1(one) voter shall be allowed to stand in front of each polling official maintaining social distance.
- xviii. Hand gloves shall be provided to the voter, for signing on the voter register and pressing button of EVM for voting.
- xix. Sanitizers shall be kept inside the booth at appropriate locations with clear direction for the use by voters.
- xx. COVID patients and all other who may be under quarantine will be allowed to cast their vote **at the last hour of the poll day** at their respective Polling Stations, under the supervision of health authorities, strictly following COVID-19 related preventive measures. Sector Magistrates shall coordinate this activity in their allocated polling stations.

37. **Postal Ballot**

Option of Postal Ballot facility has been extended to the electors of following categories:

- i. Electors who are flagged as Persons with Disabilities (PwD) and who are having benchmark disabilities.
- ii. Electors above the age of 80 years
- iii. Electors employed in notified essential services
- iv. Electors who are COVID positive/suspect and in quarantine (home/institutional)

38. **Strong-room Arrangement**

- I. Strong Room should be sanitized before the storage of polled EVMs.
- II. Social Distancing and other safety norms shall be followed for each activity.

39. **Counting of votes**

- At entry of Counting Hall there must be facility of Thermal Scanning and Sanitizer.
 - Counting Centers shall be disinfected before and after the counting.
 - Counting Hall be sufficiently big to maintain social distancing, proper ventilation, windows, exhaust fan etc.
 - Anyone, even after double vaccinated, having any symptom of COVID like fever, Cold etc. will not be allowed in Counting hall.
 - Every Counting Official and Security personnel be provided with Mask, Sanitizer, Face-Shield and Hand Gloves.
- I. Not more than 7 counting tables should be allowed in a counting hall. Hence, counting of votes of a constituency may be considered at 3-4 halls by appointing additional Assistant Returning Officers. (In supersession of instructions dated 30th April, 2014)
- II. The counting centers shall be disinfected before, during and after the counting.
- III. For counting of Postal Ballots, additional number of AROs may be required. If required, Postal Ballots may also be counted in a separate hall under the supervision of the Returning Officer/Assistant Returning officer.
- i. DEO shall appoint a Nodal Officer at each Counting Centre to ensure compliance of COVID guidelines with assistance of Nodal Health Officer and Compliance Certificate in r/o Counting Centre arrangement as per COVID guidelines from Health Authorities be taken.
 - ii. List of counting agents be made available by candidates to RO by 1700 hours on day three days prior to counting.
 - iii. No public gathering outside the counting venue during process of counting.
 - iv. Candidate may appoint/replace counting agents in case report is positive.

Needless to add that anybody violating instructions on COVID-19 measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable, as specified in Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 29th July, 2020 of Ministry of Home Affairs. District Election Officer should bring this to the notice of all concerned.

Further , the Chief Secretary cum Ex officio chairperson of the State Executive Committee under section 20 of the DM Act, 2005 shall , as and when required and as per the evolving/ contextual needs of the State, at

once bring to the notice of the Commission any new trend, development / situation that is not covered by these **broad guidelines for General Elections** and warrants Commission's intervention during the electoral process in the state so as to enable Commission to issue further appropriate instructions with respect to electoral process and thereby complementing the mandate/ efforts of the State Executive Committee in containing/ managing the spread of pandemic.

प्रेषक

संख्या- 18 /xxxi(15)G/22-04(सा0)/2020

विनोद कुमार सुमन
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 13 जनवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव सुनिश्चित किये जाने हेतु अग्रिम आदेशों तक निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी:-

1. ऐसी महिला कार्मिक, जो गर्भावस्था में हों अथवा 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, घर से ही (Work from Home) कार्य करेंगे। इनको अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जा सकेगा।
2. राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों (Essential Service में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालयध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है।
3. शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।
4. जो कार्मिक विधान सभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी में लगाये गये हैं अथवा जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात हैं उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। निर्वाचन ड्यूटी में लगाये गये कार्मिकों के बारे में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के बारे में उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जनहित में अपने विवेक से समुचित निर्णय लिया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

13/1/22

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या— /xxxi(15)G/22-04(सा0)/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड को मा. मंत्रीगण महोदय के सज्जानार्थ।
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)।